

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न

पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से  
संबंधित है।

द हिन्दू

22 दिसम्बर, 2020

के.पी. ओली ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता के हित को खतरे में डाल दिया है।

नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की संसद को भंग करने की सिफारिश, जिसे विधिवत रूप से राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है, ने युवा लोकतंत्र को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल की ओर धकेल दिया है। श्री ओली, जिनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का संसद में दो-तिहाई बहुमत है, ने अपनी पार्टी द्वारा पिछले हफ्ते जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेने के दबाव में आने के कारण कठोर कदम उठाया है।

विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के भीतर अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि संवैधानिक परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया अध्यादेश प्रणाली में रोक और संतुलन को कमजोर करेगा और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने में प्रधानमंत्री को सशक्त करेगा। श्री ओली ने पार्टी की एक बैठक में अध्यादेश को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन रविवार को, उनके मंत्रिमंडल ने संसद को भंग करने की अप्रत्याशित कदम उठाया। अब निर्धारित शेड्यूल से एक साल पहले अप्रैल-मई 2021 में चुनाव होंगे।

संवैधानिक विशेषज्ञों ने श्री ओली के निर्णय की वैधता को चुनौती दी है। नेपाल का 2015 का संविधान सदन को उसके पांच साल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही भंग करने की अनुमति देता है, अगर कोई त्रिशंकु विधानसभा हो और कोई पार्टी सरकार बनाने का प्रबंध नहीं करती है। चूंकि राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है, इसलिए अब इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

संसद भंग होने के बाद नेपाल में कई जगह पीएम ओली और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। इधर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित नेपाल के धनगढ़ी शहर समेत अन्य कई स्थानों पर ओली का पुतला दहन किया गया। राजनैतिक उथल-पुथल के चलते इस बीच नेपाल में माओवादी गतिविधियों के तेज होने की आशंका बढ़ गई है। जिसके चलते इंडो-नेपाल बार्डर पर सतर्कता बढ़ाई गई है।

नेपाल में 90 के दशक में माओवादियों ने देश में लोकतंत्र कायम करने और एक नए संविधान की मांग करते हुए हथियार उठा लिए थे। 10 साल तक चले गृहयुद्ध का अंत 2006 में एक शांति समझौते से हुआ। इसके दो साल बाद नेपाल में संविधान सभा के चुनाव हुए जिसमें माओवादियों की जीत हुई। साथ ही, 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया।

मगर मतभेदों की वजह से संविधान सभा नया संविधान नहीं बना सकी और कार्यकाल का कई बार विस्तार करना पड़ा। आखिरकार 2015 में एक संविधान को स्वीकृति मिल पाई। हालांकि नेपाल में लोकतंत्र बहाल तो हो गया पर उसमें लगातार अस्थिरता बनी रही। नेपाल में संसद बहाल होने के बाद से अब तक दस प्रधानमंत्री हुए हैं।

जब 2017 में श्री ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (UML) और इसके सहयोगी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, तो कई लोगों को उम्मीद थी कि यह एक नई शुरुआत होगी। नेपाल का एक राजतंत्र से एक प्रजातंत्रीय लोकतंत्र तक का सफर काफी दर्दनाक रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में सीपीएन-यूएमएल और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) ने एक साल से भी कम समय में देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट फोर्स, एनसीपी का गठन किया।

यह राकांपा के लिए, विशेष रूप से श्री ओली के लिए, अपने कई संकटों से भागते लोकतंत्र को खत्म करने का एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन विलय ने एनसीपी के दो गुटों के बीच बुनियादी अंतर को भंग नहीं किया। श्री ओली के सत्तावादी आवेगों और माओवादी गुट के साथ सत्ता साझा करने से इंकार करने से मामला और बिगड़ गया।

हाल के महीनों में, श्री ओली को पद छोड़ने के लिए राकांपा के भीतर से मांग उठी। जब पार्टी ने उनसे संशोधन वापस लेने के लिए कहा, तो यह स्पष्ट था कि उन्होंने आंतरिक समर्थन खो दिया था। लेकिन पार्टी का अनुसरण करने के बजाय, श्री ओली ने अपनी सरकार को ढूबाने का फैसला किया। संकट की गंभीरता को देखते हुए, विभाजन को खारिज नहीं किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है, तो नेपाल धीमी अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोनावायरस संकट जैसे चुनौतियों के बीच, राजनीतिक अस्थिरता की ओर चला जाएगा।

### संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नेपाल का संविधान वर्ष 2015 में लागू हुआ था।
2. नेपाल, भारत के 5 राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (a) केवल 1       | (b) केवल 2         |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1, न ही 2 |

### Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:-

1. The Constitution of Nepal came into force in the year 2015.
2. Nepal shares a border with India's 5 states Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Sikkim and Bihar.

Which of the above statements is/are correct?

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| (a) Only 1       | (b) Only 2          |
| (c) Both 1 and 2 | (d) Neither 1 nor 2 |

### संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान में भारत-नेपाल संबंध के बीच व्याप्त चिन्ताओं के मुख्य कारकों पर चर्चा करते हुए नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. While discussing the main factors of concern prevailing in the India-Nepal relationship, discuss the main effects of Nepal's political instability on India. (250 Words)

**नोट :-** अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।